



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii) OF INDIA

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 1989/श्रावण 19, 1911
No. 495] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 1989/SRAVANA 19, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग संश्लेष

(कंपनी कार्य विभाग)

प्रशिक्षण

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1989

का. मा. 528(प्र):—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक-हित में सेवा करना आवश्यक और
सामंजस है।

प्रब. अतः केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा प्रबोधिषक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 5
के उपनियम (5) और नियम 6 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार
के अन्तर्गत विधि, न्याय और कंपनी कार्य संश्लेष, कंपनी कार्य विभाग की प्रशिक्षण सं. 566(प्र),
तारीख 17-7-81 की अधिसूचना करते हुए, उन प्ररूप की जिसमें उद्योग (विकास और विकास) अधिनियम,

1951 (1951 का 63) के अधीन शक्तिशालि निर्यातनमुखी उपक्रम की स्थापना या पर्याप्त विस्तार के लिए कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापन किया जाना अपेक्षित है, उस प्ररूप के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प मं. 8(15)/78-एल पी. तारीख 31-12-80 में यथापरिभाषित किसी शक्तिशालि निर्यातनमुखी उपक्रम से संबंधित किसी प्रस्ताव की बाबत एकाधिकार तथा प्रबोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना, यथास्थिति, री जाणगी या धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाएगा।

[का. म. 5/26/89—एन-1]

एल. सी. पोखरा, प्र. मंत्रालय

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 1989

S.O. 628(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 5 and sub-rule (3) of rule 6 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, and in supersession of the notification of the Government of India (No. 566(E), dated 17-7-81) in the then Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Company Affairs, the Central Government hereby specifies the Form in which an application for a licence or permission for the establishment or substantial expansion of hundred percent Export Oriented Undertakings is required to be made under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), as the Form in which a notice under sub-section (1) of section 21 or an application under sub-section (2) of section 22 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), shall be given or made, as the case may be, in respect of any proposal relating to a hundred percent Export Oriented Undertaking as defined in the resolution of the Government of India, in the Ministry of Commerce No. 8(15)/78-LP, dated 31-12-80 as amended from time to time.

[F. No. 5/26/89-M. I.]

L. C. GOYAL, Dy. Secy.